

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, बनड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

अधीकारी - श्री रतन लाल रेगर, (आर.ए.एस.)

संख्या : 82/2010 राजस्व वाद

उनवान

पोखर कुम्हार पुत्र श्री सवाईराम कुम्हार (प्रजापत) निवासी खेडलिया, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

— (वादी)

बनाम

बालु पुत्र श्री भुरा कुम्हार (प्रजापत), निवासी खेडलिया, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

मुच पुत्र श्री केला कुम्हार (प्रजापत) निवासी खेडलिया, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 92(क) आर0टी0ए0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.

उपस्थित -

- 1. श्री दिनेश कुमार जोशी (अधिवक्ता वादी)
- 2. श्री अनित कोठारी (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01)

दिनांक- 20-4-2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विपक्षीसंख्या 01 के ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस दिनांक 23.03.2017 को सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर मेन्टेनेबल न होकर काबिले प्रतिवादी के है। वादी पोखर द्वारा एक वादपत्र पूर्व में दिनांक 22.06.1970 को उपखण्ड भीलवाडा अन्तर्गत धारा 53, 54 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादी भूरा व अपने अन्य धर्म के बतौर प्रतिवादीगण संयोजित करते हुए साबिक आ0 सं0 51 रकबा 15.06 बीघा वाके खेडलिया बाबत विभाजन आराजियात प्रस्तुत किया, जिसके वाद प्रकरण संख्या 94/70 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 18.11.74 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री मुर्तिब हुई। प्रस्तुत विवादित आराजियात पर वादी के हक हिस्से पर वादी का कब्जा न होने से विभाजन प्रकरण नहीं हो सका इसके पश्चात वादी द्वारा प्रारंभिक डिक्री में संशोधन किये जाने बाबत आदेश अन्तर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. दिनांक 09.06.88 को प्रस्तुत कर विभाजन के प्रकरण का कब्जा दिलाये जाने की दाद भी हासिल करनी चाही, तत्पश्चात दिनांक 25.11.91 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 152, 153 सी.पी.सी. स्वीकार होकर संशोधित डिक्री पर्चा मुर्तिब हुआ उसी दिनांक से विवादित आराजियात के नवीन नम्बर कायम होकर वादी के हक हिस्से में आदेश संख्या 138, 137, 138, 149 रकबा 6.14 बीघा नवीन नम्बर कायम हुए। इसके पश्चात दिनांक 17.09.92 को मुताबिक डिक्री पर्चा दिलाये जाने कब्जा आदेश संख्या 214/92 एवं न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पश्चिम भीलवाडा में चालान संख्या 447 ना0दं0सं0 के तहत दोषमुक्त घोषित किया जाकर प्रकरण निर्णित

इस प्रकार एक ही वाद विषय, आराजियात व उन्ही पक्षकारों के मध्य दुबारा वाद कर अनुतोष चाहना धारा 11 जा0दि0 के तहत प्रतिकूल होकर इसके अतिरिक्त स्पष्टतः न्यायाद होकर अन्दर अवधि नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाकर वादी का वाद पत्र मंटेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में इंगित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र प्रथम खारिज किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुती बाबत अंतिम अवसर प्रदत्त किया जावे। इस के दौरान वादी अधिवक्ता ने अपने तर्कों से अवगत कराया कि पूर्व का वाद पत्र सलंगन बाबत था ओर मौजूदा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 92 क आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कि भिन्न भिन्न धाराओं में प्रस्तुत किये गये है, तथा वादग्रस्त विषय पर वादी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत दावा को पुनः वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किया जाना फरमावे।


अभियन्तों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व सलंगन तथा वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बहस में समायत तर्कों व साक्ष्य के तोर पर सलंगन दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा समान वाद विषय, आराजियात व उन्हीं पक्षकारों के मध्य दुबारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि न्यायिक दृष्टिकोण से धारा 11 जा0दी0 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिकूल होने से वादी का वाद पत्र पोषणिय नहीं होकर खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त वाद पत्र अन्दर अवधि नहीं होकर गैर मियाद होने से काबिले खारिजि है। इसके अतिरिक्त तथ्यों पर वादी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस प्रतिरोध में अपने तर्कों से कोई भी दावा के रूप में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कराया है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि वास्तव में वादपत्र सलंगन दस्तावेजात चलने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मंटेनेबल नहीं होने व बैरूम मियाद होने से खारीज कर आदेश प्रसारित किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वयं वहन करें।

दिनांक 2014/17

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की


(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा